~~आर्थिक मंदी [illegible] मुकाबले की ओर~~
~~बड़ी आर्थिक मंदी के गर्त में~~

(आज) दुनिया का [illegible]
आपदा के दौरान वाणिज्य स्थगन,
रक्षित नगरों ने निर्णीत निवेश —
मांग पक्ष (स्मरण नहीं दिया)
के
१०-२० करोड़ लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं [illegible] (के [illegible] पारिवारों)
बेरोजगारी [illegible]

~~विश्व बाजार मंदी~~ [illegible]
२००९ की मंदी से बड़ी प्रथम [illegible]
१९३० से बड़ी आर्थिक मंदी —
[illegible] [illegible], [illegible] —
वर्ष का काम [illegible], [illegible] ४% का नुकसान,
कुल ३ [illegible] ३% से [illegible]
२०२० में ६ करोड़ गरीबी रेखा से नीचे
विश्व बैंक का अनुमान है [illegible] के [illegible]
[illegible] गरीबों को [illegible] सहायता [illegible]
[illegible] दुनिया में [illegible]
१२० का कहना है — [illegible]
३३० करोड़, इनमें २०० करोड़ [illegible] [illegible]
[illegible], इनमें ६०% [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] है।
[illegible] [illegible] [illegible] है
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ने [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] नहीं।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

GDP और विकास दर को लेकर अनुमान निराशाजनक है।

NCAE के अनुसार जीडीपी में 25% तक गिरावट आएगी।

21-22 की कुल प्राप्ति कम रहेगी।

GDP में 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष में 20-30 लाख करोड़ रुपये की गिरावट

हमारे कारोबारी इकाइयां व [illegible] बंद हो रही हैं। वहीं कोरोना से बेरोजगारी, [illegible] घट रहा है। होती जा रही है मूल्य [illegible]

GST के कारण राज्यों [illegible] 6.5 लाख करोड़ [illegible] 28 लाख करोड़ को [illegible] मिला है। [illegible] पात है।

पूंजीवाद को [illegible]

पूर्विक्षण सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 93% श्रमबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत। प्रवासी [illegible] 47.15 करोड़ कामगार हैं इनमें सर्वेक्षण के अनुसार [illegible] 11.42 करोड़ ही नियमित वेतन पाने वाले हैं। [illegible] 14.41 करोड़ [illegible] 24.23 करोड़ [illegible] हैं।

[illegible] कृषि [illegible] 5 करोड़ [illegible] लगाते हैं। [illegible] 90% महिलाएं हैं। [illegible] 5 करोड़ [illegible] हैं।

सहायता [illegible] 4 लाख करोड़ [illegible] मजदूरों की [illegible] हुई है।

प्रवासी [illegible] गांवों में मनरेगा है। [illegible]

+2 IMF [illegible] 30 करोड़ [illegible] नौकरियां [illegible] हुई। [illegible] में 35 [illegible] नौकरियां [illegible] हैं

+1 [illegible] कामगारों में [illegible] हुआ है [illegible] करीब 1.5 लाख [illegible] 40% [illegible] के वेतन में कटौती

लॉकडाउन में ढील देने के बाद तेजी से वित्तीय
लेन देन बढ़ा है। जुलाई में इजाफा हुआ है
कुल 3 लाख न, रेल
Corporate Bond Issue में 95.1%.
वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा कोष बढ़कर
507.6 अरब डालर हुआ है। भारतीय रिज़र्व.
गेहूं की 3-8 करोड़ टन 73.5 करोड़
42 लाख किसानों को
भुगतान हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत की
विकासशील बना देगी
भारत नहीं बन रहा।
2020-21 में 4.5% नकारात्मक. (पूर्वानुमान) IMF मुद्राकोष
विश्व बैंक 3.2 4.5 की नकारात्मक वृद्धि
India 4.5% मैन्युफैक्चरिंग
प्राथमिक की लॉकडाउन पहले से बीमार।
18-35% का संकुचन हुआ है
लॉकडाउन सामाजिक दूरी के विशेष उपाय से
बाद में - 3 लाख करोड़ का पैकेज ... प्रतिकूल प्रभाव।

20
IMF.
अन्तर्राष्ट्रीय Rating Agency. 5% नकारात्मक.
India Rating ने 5.3 संकुचन, नकारात्मक वृद्धि.
इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट -5.2% होगी.
20.97 लाख करोड़ का प्राथमिक पैकेज में
केवल तरलता (नकदी) बढ़ाने पर ज्यादा जोर है
अर्थव्यवस्था मांग के अभाव से पीड़ित है।
जिनमें श्रमिक उपयोग (वर्ग), सब कारखानों की पूंजी, निर्माण
निर्यात क्षेत्र से जुड़ा है) सरकारी प्राथमिकताओं में
गिरावट की वजह से बाजार में उपलब्ध
अ. वास्तव में नहीं आ सकेगी।

सरकारी धारा
लक्ष्य में ज्यादा
मितव्ययता के लिए
सरकारी खर्च को
से बचा गया।
कमजोर लोग से
जेबों का मानवता
बनाए रखा गया।

5 કરોડથી વધારે રોજગાર(લોકો) (CMI) ને 33 ટકા

Aviation, Hospitality, Education, વિગેરે,

રાષ્ટ્રીય વ્યવસાયોમાં નિમણૂકો મહત્વ

Hotel Restaurant

યુવાઓ, યુવાનો વધારે

સફળતાથી

ટેકનોલોજી રોજગારી

નવા રોજગાર

ગામો માટે Package.

સ્કૂલ - ગામડાઓ માટે

વાહનો - ઉદ્યોગ - ઇન્ટરનેટ વિગેરે

Public Transport વધારવા

સાથે રોજગારી, રસ્તો

રસ્તાઓ બાંધવા

રોજગારી વધારવી.

13 કરોડ —

40 % વધારો

3.25

રાષ્ટ્રીય ...

Office.

आर्थिक विषमता की अनदेखी

सत्यनारायण देव

(1)

एक अन्तरराष्ट्रीय एनजीओ ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष असमानता की जमीनी हकीकत सामने आई है। के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी है। अमीर गरीब की खाई बढ़ी है। जहां अमीर मालामाल हो गये, गरीब कंगाल हो गये। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विषमता की अनदेखी कौन से, मात्र एक नारा बनकर रह गया। 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां गईं। 1.7 करोड़ महिलाओं की नौकरी छिन गई। 1.7 लाख लोगों की नौकरी गई या रोजगार, 84% घरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। इस दौरान भारत में मुकेश अंबानी ने जितना कमाया उतना कमाने में मजदूरों को 10 हजार साल लगेंगे।

महामारी के बाद भारतीय अरबपतियों में असमानता जो आर्थिक [illegible] की दुनिया [illegible] उत्पादन पहुँच गई है [illegible] गुलामी का)

अरबपतियों की सम्पत्ति 90 फीसदी 2009 से अब तक बढ़कर 422.9 अरब डालर हो गई। भारत अरबपतियों की सम्पत्ति के मामले में विश्व में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस व फ्रांस के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया है। यह ऐसे समय हुआ जब अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद मंदी में डूबी थी। अधिकांश लोगों को आजीविका का नुकसान उठाना पड़ा है।

प्राइस की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कोविड 20,000 रुपये से कम कमाने वालों की 37% व 60000 रुपये कमाने वालों की 2020 में 84 फीसदी 10% आय कम हुई। आय का सामना करना पड़ा है।

प्रतिमाह

परिवारों की आय का हर महीने के हिसाब से 1.70 लाख लोगों ने 2020 में 167 लोगों ने मार्च से नौकरी गंवाई।

जुलाई 2020 के बीच नौकरी छूटने, आय में कमी से गुजरना और आर्थिक सेक्टर के कारोबारी खुदकुशी करली| रोजगारों के जीवन और देश के भविष्य को प्रभावित करने वाला यह अत्यन्त भयावह [illegible] है| मंदी, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई ने विषमता को बढ़ाया| सबसे अधिक प्रभाव गरीब व हाशिये पर चल रहे सामाजिक समूहों के बच्चों पर पड़ा है, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के बच्चे बालश्रम में बढ़ रहे हैं| अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों, आदिवासियों के बच्चों स्कूल छूट गये, उनमें कुपोषण बढ़ा है| आमलोगों के लिए निर्धनता, पेयजल, ईंधन की कमी, [illegible] व हिंसा की बढ़ोतरी से जाति का भविष्य दांव पर है| असमानता की खाई [illegible] गुनी बढ़ गई है|

एक सौ अरबपतियों की संपत्ति मार्च से गत महिनों में 12.97 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, इस राशि से भारत की एक सौ चालीस करोड़ आबादी में हर व्यक्ति को चौरानवे हजार रुपये दिये जा सकते हैं| सरकारी योजना मनरेगा दस साल तक चलाई जा सकती है| सरकार ने इन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया दूसरी ओर गैस, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर जनता से वसूली कर रही है| असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 90 फीसदी आबादी में चालीस फीसदी लोगों पर और गरीबी में चले जाने का खतरा है| निम्न आय वाले तबके 46 फीसदी लोगों ने कर्ज लेकर गुजारा किया है| फीसदी गरीबों का कर्ज लेकर शिक्षकों करना पड़ा है| ~~[illegible]~~ सहित ज्यादा देश के सौ से ज्यादा नौसौ चालीस के प्रमुख पूंजीपतियों पर आर्थिक

वाली सम्पदा पर कर लगा दिया जाता तो देश की
जीडीपी की एक प्रतिशत के बराबर रकम हासिल हो जाती।
विश्व आर्थिक मंच में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अगर
भारत के ग्यारह सबसे अमीर खरबपतियों की गत एक साल
में बढ़ी आमदनी पर सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स ले लिया
जाय तो देश की जन औषधि योजना एक सौ चालीस गुना
बढ़ती या फिर गरीबों के लिए एक सौ चालीस नई
योजनायें शुरू की जा सकती थीं। छोटे से धनवान
तबके से न्यायोचित मात्रा में धन लेकर बहुत बड़े
गरीब तबके तक पहुंचाने से आर्थिक विषमता की खाई
पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।
अपेक्षित बदलाव न हो पाने का कारण नीतियों का
अभाव, ~~[illegible]~~ अन्तर्निहित नीतियां व क्रियान्वयन में
खामी है।

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधार
व बदलाव का अपेक्षित प्रसार नहीं दिखता तो
शहरों में अनियोजित विकास है। नीति नियंताओं ने
अग्रगामी सोच के विकास के लिए न तो कोई ठोस
मानक बनाये और न ही दूरदर्शिता का परिचय दिया
[illegible] अग्रगामी सोच का खामियाजा दिख रहा है।
इस कारण [illegible] टैक्स वसूली के बजाय छूट दी जा रही है
पूंजीपतियों से [illegible] हाथों बेची जा रही है।
सरकारी सम्पत्तियां उन्हीं के [illegible] बदलाव की दिशा
सकारात्मक सोच के साथ [illegible] नीतियां बनाई जा रही हैं
[illegible] के बजाय [illegible] मानसिक सेहत
बढ़ती बीमारियों की [illegible] पर्यटन, रियल एस्टेट
बिगड़ रही है [illegible] हो गये हैं। पेट्रोल डीजल
में [illegible] रोजगार [illegible] प्रतिदिन हो चुका है
क्रमशः 97.17 व 81.47 रुपया प्रति लीटर हो चुका है
किसान, मजदूरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है
महामारी ने गरीबों को सर्वाधिक कष्ट
पहुंचाया है और आर्थिक विषमता को बढ़ाया है, असमानता को
[illegible] बेरोजगारी [illegible] बढ़ाया है, पुनः बढ़ती सामाजिक उथल-पुथल बढ़
सकती है।

प्रभाव पड़ता है

(1) छलती प्रसन्नता

विकास का लाभ किसे ? 1922 में

सरकार का दावा है अर्थव्यवस्था के ~~9.5~~ 8.5 फीसदी की
दर से बढ़ने के अनुमान है। ~~प्रति~~ जीडीपी की ~~वृद्धि~~ ग्रोथ रेट
पहली बार 20.1% दर्ज हुई है। अक्टूबर में सेंसेक्स 67,245
की ऊंचाई तक पहुंच गया है। कोरोना के मद्देनजर लगे लॉकडाउन
के हटने के बाद मांग में बढ़ोत्तरी हुई है पर आपूर्ति श्रृंखला
बहाल नहीं हो पाई। महंगाई लगातार बढ़ रही है। पिछले 12
महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है, थोक महंगाई 22.35 प्रतिशत
[illegible]
लोग महंगाई की तपन महसूस कर रहे हैं। दालें 30%, कारन 51%, इस प्रकार क्रूड
सोयाबीन तेल 52%, पाम ऑयल 30% फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। ~~कच्चा~~
प्राकृतिक गैस में 27.3 फीसदी की बढ़ोत्तरी, ... 32.37% कुकिंग
एक साल में कच्चा तेल 59.54, स्टील 90%, ... 106%
कोयला 118.24% महंगा हुआ है। ... 28% महंगे हुए हैं। पेट्रोल
तांबा, एल्यूमिनियम, निकल 22 से
डीजल महंगा हुआ है। इस प्रकार एक साल में खासा महंगाई आतंक
14%. ~~... महंगाई 27% प्रतिशत हुई है~~ पिछले 12 साल में
उच्चतम महंगाई का प्रभाव सबसे ज्यादा गरीब वर्ग पर
पड़ा है। ... क्रय शक्ति कम हुई है, ... उपभोक्ता ... ग्रामीण
2020-21 में खुदरा महंगाई 6.2% ...
उपभोक्ता में 9% ... संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ... महंगाई के प्रभाव
के ... दुनिया में 4 में से 3 लोग ... 1.8 ...
को महसूस कर रहे हैं
[illegible] ... 8.24% ...
देश में प्रति व्यक्ति आय
... 99,694 रुपये। 2019-20 में 1,08,645
की व 2018-19 में 1,05,526 थी ... बेरोजगारी
पेट्रोल में 11.84 फीसदी ... पहुंच गई। ... प्रतिशत ... बेरोजगारी
तुलनात्मक देशों की ... तेजी से ... 3 ...
क्रूड प्राइस की कीमत में ... पेट्रोलियम की कीमतों
आसमान, रसायनिक खाद, ... पर प्रभाव पड़ा।

—2—

परिवहन की लागत में ~~वृद्धि~~ बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक वस्तुओं की
कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तेल की कीमतों में तेजी आई।
मंहगाई की वजह से आपूर्ति में बदलाव हुआ है।
मंहगाई के बाद उपभोक्ताओं को कीमतों से
बेरोजगारी की समस्या पैदा की गई है। हर क्षेत्र में
नहीं जा पा रहा पनप रहा है। विकास का लाभ नीचे तक नहीं
पहुंच रहा है। सरकार द्वारा गैर उत्पादक कार्यों पर खर्च
बढ़ाया जा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस के
अनुसार भारत में नीचे की आबादी का गरीबी स्तर
वहीं है जो 1932 में यानि महामंदी के तत्काल बाद अमेरिका
अमेरिका के 50% नीचे के वर्ग में था। गरीबी में इस अमेरिका
से 90 साल पीछे हैं। आजादी के बाद जो स्थिति में सुधार
हुआ है वह गत 3-4 वर्षों में समाप्त हो गया। इसमें
गरीबों का ध्यान देने का संकल्प लिया, 1970 में गरीबी
हटाने का नारा दिया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द
जोड़ा। गरीबों का उत्थान का लक्ष्य बनाया। जो कुछ काम
हुआ उसका असर वर्तमान नीतियों के कारण समाप्त हो गया
सन 2014 से वर्तमान सरकार के पहले 30 वर्षों में
सबका विकास का नारा दिया। ~~लेकिन~~ आजादी के सालाना प्रति माह 2.2%
आधी आबादी की वास्तविक आय बढ़ी रही। निचले प्रतिशत
रही। 45 साल तक यही पर बनी रही। दुनिया के
विकासशील प्रतिशत सेन के मुताबिक भारत दुनिया के असमानता वाले देशों में प्रमुख है।
सबसे अधिक आर्थिक असमानता पहले शुरू हुआ तो भारत
मानव विकास सूचकांक में 3 साल पहले हुए जबकि भारत
विकास
135 वें स्थान पर था। देश की आबादी का लाभ नीचे तक
जोड़ी प्रयासों में विकास का लाभ वंचितों की
106 स्थान पर है। वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण
नहीं पहुंच रहा है। वर्तमान सरकार नीतियों
नीतियां कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ रही हैं। भारत की स्थिति
असमानता इण्डेक्स में विश्व के 149 देशों
संतोषजनक नहीं है। स्थान में आखिरी देशों

139 रही, जो पिछले वर्षों के मुकाबले मामूली सुधार है।
सरकार की नीतियां प्रो रिच है, दलित गरीब किसान ग्रामीण
जंगल जमीन, मुफलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी से
संघर्ष कर रहा है, उन उत्पादक कामों को दरकिनार
किया जा रहा है। विकास के नाम पर पूंजीकरण किया जा
रहा है। देश की सम्पत्ति व पूंजी का [illegible] बढ़ रही है
मात्र कुछ उद्योगपतियों को मिल रही है। असमानता बढ़ रही है। पेट्रोल
क्योंकि विकास का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। [illegible]
डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। [illegible]
कम नहीं। कीमतें [illegible] किया गया है। [illegible] कुल मिलाकर
जनता को [illegible] का [illegible] रहा है। [illegible]
का [illegible] है [illegible] भारतीय [illegible]
पुन भारतीय [illegible]
विकास [illegible] है।
[illegible] का [illegible] होता जा रहा है।